



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 31 मार्च, 2004/11 चैत्र, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

अधिसूचना

शिमला, 25 मार्च, 2004

संख्या एच० पी० डी० आर० सी०/021.—निम्नलिखित प्रारूप विनियम, जिन्हें हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 87 के साथ पठित, धारा 181 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 181 की उप-धारा (3) द्वारा यथोपेक्षित के अनुसार उनसे ग्राम प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं; और एतद्द्वारा यह नोटिस (सूचना) दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिन के अवसान पर, किसी भी आक्षेप या सुझाव सहित, जो इस बादत उक्त अवधि के भीतर प्राप्त हुआ हो / हुए हों, पर विचार किया जाएगा।

इस निमित्त आक्षेप या सुझाव, सचिव, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, क्योथल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, खलीनी, शिमला-171002 को सम्बोधित किए जाने चाहिए।

प्रारूप—विनियम

भाग—1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004 है।

(2) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) “कार्य-सूची” से राज्य सलाहकार समिति की बैठक में कारबार संव्यवहार हेतु प्रस्तावित कार्य-सूची अभिप्रेत है;

(ग) “अध्यक्ष” से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) “आयोग” से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) “समिति” से राज्य सलाहकार समिति अभिप्रेत है;

(च) “समिति सदस्य” से आयोग के सदस्य से भिन्न राज्य सलाहकार समिति का सदस्य अभिप्रेत है;

(छ) “सदस्य” से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है।

(2) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु यहां परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होगा जो कि उन्हें अधिनियम में नियत किया गया है।

भाग—2

समिति का गठन तथा कृत्य

3. राज्य सलाहकार समिति का गठन.—(1) राज्य आयोग, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से जो यह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, एक समिति गठित करेगा जिसे, राज्य सलाहकार समिति कहा जाएगा।

(2) राज्य सलाहकार समिति, विद्युत सैक्टर में निम्न हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इक्कीस से अनाधिक नामनिर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर बनेगी :—

(क) वाणिज्य;

(ख) विद्युत उद्योग;

(ग) परिवहन;

(घ) कृषि;

(ङ) श्रम;

(च) उपभोक्ता;

(छ) गैर-सरकारी संगठनों;

(ज) विद्युत सैक्टर में शैक्षणिक तथा अनुसंधान निकायों।

(3) सदस्यों के नाम निर्देशन से पूर्व, आयोग, यदि आवश्यक समझे, हित प्रतिनिधियों या गुप्तों से परामर्श कर सकता है।

(4) समिति के निम्न पदेन सदस्य होंगे :—

- (क) आयोग के अध्यक्ष;
- (ख) आयोग के सदस्य;
- (ग) उपभोक्ता मामले तथा लोक वितरण प्रणाली में सम्बन्धित मन्त्रालय या विभाग का भारमाधक राज्य का सचिव।

(5) आयोग अध्यक्ष समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

(6) आयोग सचिव समिति का पदेन सचिव होगा।

(7) उप-विनियम (2) के अधीन नाम निर्दिष्ट समिति सदस्यों की पदावधि, उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से, दो वर्ष की होगी :

परन्तु नाम निर्दिष्ट सदस्य पुनर्नामनिर्देशन का पात्र होगा।

4. राज्य सलाहकार समिति के कृत्य.—समिति निम्नलिखित के सम्बन्ध में राज्य आयोग को सलाह देगी—

- (क) नीति सम्बन्धी मुख्य प्रश्न;
- (ख) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की क्वालिटी, निरन्तरता और विस्तार से सम्बन्धित विषय;
- (ग) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उनकी अनुज्ञप्तियों की शर्तों और अपेक्षाओं का अनुपालन;
- (घ) उपभोक्ता हित का संरक्षण;
- (ङ) विद्युत प्रदाय और उपयोगिताओं द्वारा निष्पादन के समान मानदण्ड; तथा
- (च) ऐसे विषय जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं।

भाग—3.

बैठकें

5. समिति की बैठकें.—समिति अपने कारखारसंयवहार हेतु प्रत्येक छः मास में एक बार तथा ऐसे अन्तराल पर, जैसे अध्यक्ष विनिश्चित करे, बैठक करेगी।

6. बैठक स्थल.—समिति की बैठकें ऐसे स्थान पर, जैसे अध्यक्ष विनिश्चित करे, होंगी।

7. बैठक की कार्य-सूची तथा सूचना.—(1) आयोग सचिव, अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात्, सूचना, विवरण तथा रिपोर्ट, यदि कोई हो, सहित कार्य-सूची भेजकर और सदस्यों/समिति सदस्यों को प्रस्तावित बैठक की तारीख, समय तथा स्थान का नोटिस, जो चौदह दिन से कम का न हो, देकर समिति की बैठकें बुलवाएगा।

(2) सदस्य संक्षिप्त टिप्पण द्वारा, विनियम 4 में निर्दिष्ट किसी विषय का उल्लेख करते हुए, पश्चात्पूर्व बैठक की कार्य-सूची में सम्मिलित करने के लिए सचिव को लिख सकेंगे और यदि अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञात हो, उसे विनियम (1) के अधीन परिचालित की जाने वाली कार्य-सूची में सम्मिलित कर दिया जाएगा।

(3) अध्यक्ष विशेष बैठक बुलवा सकेंगे तथा उस दशा में बैठक का नोटिस तीन दिन से कम का भी हो सकेगा।

(4) यदि नोटिस (सूचना) सदस्य, समिति के रजिस्ट्रार पत्र पर, विहित समय के भीतर, डाक द्वारा या संश्लेष-पात्र के माध्यम से, भेजा जाता है तो वह सम्यक् रूप से भेजा गया समझा जाएगा ।

8. बैठकों में गणपूर्ति एवं चर्चा.—(1) बैठक की गणपूर्ति समिति की कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई होगी :

परन्तु समिति की बैठक में प्रोक्षी (प्राक्सी) उपस्थिति अनुज्ञात नहीं होगी ।

(2) यदि बैठक में गणपूर्ति नहीं होती तो वह स्थगित कर दी जाएगी और स्थगित बैठक की दशा में और कोई नोटिस (सूचना) तथा गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी :

परन्तु, यदि बैठक प्रारम्भ होने के पश्चात् गणपूर्ति नहीं रहती है तो बैठक विघटित नहीं की जाएगी और वह जारी रखी जाएगी ।

(3) स्थगित बैठक में, उस बैठक, जिसमें स्थगन किया गया था, के बकाया विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जाएगा :

परन्तु अध्यक्ष, सूचना सहित या उससे रहित, कोई नया विषय, जो उनके मत में अति-आवश्यक है, को स्थगित बैठक में ला सकेगा या लाने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा ।

(4) बैठक में चर्चा तथा उसमें लिए गए परिणामतः निष्कर्ष, यदि कोई हो, बैठक के लिए नियत कार्य-सूची के क्रमानुसार ही होंगे :

परन्तु बैठक के अन्त में अध्यक्ष कार्य-सूची पर अतिरिक्त विषय ला सकेगा ।

9. रिक्तियों तथा कार्य-सूची अप्राप्ति से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.—केवल इस आधार पर कि समिति में रिक्तियाँ हैं या किसी समिति सदस्य द्वारा नोटिस (सूचना) या कार्य-सूची, यदि नोटिस या कार्य-सूची सम्यक् रूप से जारी की गई है, प्राप्त नहीं होती है, समिति की कोई कार्यवाही या उसमें पारित संकल्प या लिया गया विनिश्चय अविधिमान्य नहीं होगा ।

10. पीठासीन अधिकारी.—(1) बैठक की अध्यक्षता तथा उसका कारबार संचालन अध्यक्ष करेगा । यदि किसी कारणवश अध्यक्ष बैठक में उपस्थित रहने में असमर्थ हो तो राज्य आयोग का ज्येष्ठतम सदस्य बैठक की अध्यक्षता तथा समिति अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेगा ।

(2) अध्यक्ष, या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य, द्वारा प्रक्रिया-प्रश्नों पर दी गई व्यवस्था अन्तिम तथा आवद्धकर होगी ।

11. बैठकों में भाग लेना.—(1) अध्यक्ष किसी व्यक्ति को, जो समिति का सदस्य नहीं है, बैठक की कार्य-सूची में किसी विषय पर समिति को सहायता और सलाह देने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमन्त्रित कर सकेगा ।

(2) सचिव और व्यक्ति, जिसे अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित होने के लिए आमन्त्रित किया गया है, अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले सदस्य की अनुमति से, चर्चा में भाग ले सकेगा ।

12. बैठक का कार्यवृत्त.—(1) सचिव, या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा प्रायोग का कोई नाम-निर्दिष्ट अधिकारी, बैठक का कार्यवृत्त अभिलिखित करेगा और ऐसी पुस्तिका रखेगा जिसमें, दूसरी बातों के साथ-साथ बैठक और कार्यवाहियों में उपस्थित सदस्यों और आमन्त्रित व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम भी दर्ज किये जायेंगे।

(2) अगली बैठक में पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाएगी तथा बैठक के अध्यक्ष द्वारा उसे हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(3) सदस्यों के सूचनार्थ अगली बैठक में आयोग द्वारा पिछली बैठक के निर्णयों के अनुपालन में की गई कार्यवाही का विवरण रखा जाएगा।

(4) कार्यवाही अभिलेख समिति सदस्यों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे।

(5) आयोग द्वारा अपने अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों की अभिप्राप्ति के लिए विहित शुल्क के संदाय पर, समिति सदस्य के इलावा, किसी भी व्यक्ति को समिति की कार्यवाहियों के अभिलेख की प्रतियां दी जा सकेंगी।

भाग—4

सदस्यों को देय शुल्क एवं भत्ते; सदस्यता का त्याग/सदस्यता की समाप्ति

13. समिति सदस्यों को देय शुल्क तथा यात्रा भत्ते.—(1) समिति सदस्यों, जिसके अन्तर्गत विनियम 11 के अधीन विशेष प्रतिथि के रूप में आमन्त्रित व्यक्ति भी शामिल है, इन विनियमों में उपबन्धित से भिन्न पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे।

(2) आमन्त्रित व्यक्ति सहित समिति सदस्य, जो सरकारी अधिकारी या किसी सरकारी परिकरण अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम का कर्मचारी/अधिकारी है, बैठक और यात्रा भत्ता अपने मूल विभाग या संस्थान से लेगा।

(3) उप-विनियम (2) में निर्निर्दिष्ट के अतिरिक्त सभी समिति सदस्यों या आमन्त्रित व्यक्ति को प्रत्येक बैठक के लिए 500 रुपये बैठक फीस तथा राज्य सरकार के ग्रुप "ए" अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(4) यहां कहीं ऐसा करना समीचीन हो, आयोग, उन सदस्यों, जो नियत बैठक स्थल से बाहर में आ रहे हों, के लिए भोजन व आवास की व्यवस्था और उन्हें निकटतम रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे से आने जाने के लिए वाहन उपलब्ध करवा सकेगा।

14. सदस्यता की समाप्ति.—(1) नामनिर्दिष्ट सदस्य, जो आयोग को पूर्व सूचना दिए बिना तथा अनुपस्थिति के लिए किसी मान्य कारण के बगैर, समिति की दो क्रमवर्ती बैठकों में उपस्थित रहने में असमर्थ होता है, तत्काल से समिति सदस्य नहीं रहेगा।

(2) कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य, आयोग के सचिव को सम्बोधित अपने हस्तालिखित-पत्र द्वारा अपने समिति सदस्य के पद का त्याग कर सकेगा और उक्त त्याग-पत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले दिन से प्रभावी होगा।

(3) आयोग, इस प्रकार से हुई रिक्ति को भरने के लिए किसी को सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए समचित कार्यवाही करेगा और इस उप-विनियम के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्य की पदावधि, इन विनियमों के विनियम 3(2) के अधीन नामनिर्दिष्ट अन्य समिति सदस्यों की पदावधि के सह विस्तारी होगी।

15. सदस्य का हटाया जाना.—(1) आयोग, पदेन सदस्यों में भिन्न, समिति सदस्यों को पद से हटा सकेगा, यदि वह,—

- (क) दिवालिया न्यायनिर्णित किया गया है ;
- (ख) किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्बलित है ;
- (ग) सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या
- (घ) उसका अपना आचरण इस प्रकार का है या उसने अपनी स्थिति का ऐसा दुरुपयोग किया है, जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित या अधिनियम के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(2) उस सदस्य को जिसे उप-विनियम (1) के अधीन हटाया जाना प्रस्तावित किया जाता है अपनी स्थिति बताते हुए आयोग के अध्यक्ष को अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जायेगा।

16. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.—(1) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) तथा इन विनियमों के अधीन रहते हुये, आयोग उन मामलों में जिनके लिए ये विनियम आयोग को निर्देश देने के लिए सशक्त करते हैं, आयोग, समय-समय पर, विनियमों के अनुपालन में तथा प्रक्रिया अपनाने हेतु एवं प्रासंगिक या आनुषांगिक विषयों पर आदेश तथा पद्धति निदेश दे सकेगा।

(2) यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को लागू करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आयोग, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी कार्यवाही, जो आयोग को कठिनाईयां दूर करने के उद्देश्य से समचीन लगती हो, कर सकेगा या समिति को करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आयोग, किसी भी समय, आदेश द्वारा, इन विनियमों के उपबन्धों में परिवर्धन, परिवर्तन, उपान्तरण व मंशोधन कर सकेगा।

(4) इस विनियम के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा पटल पर रखा जायेगा।

17. निरसन और व्यावृत्ति.—(1) विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 24 तथा 25 के अधीन 28 फरवरी, 2001 को जारी हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा राज्य सलाहकार समिति संचालन मार्गदर्शन (गाइडलाइज फॉर फंक्शनिंग आफ स्टेट एडवाइजरी कमेटी) एतद्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए, आसीन सदस्य जिन्हें निरसित गाइडलाइज के अधीन सलाहकार समिति का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया गया है, अपनी शेष पदावधि तक इन विनियमों के अधीन सदस्य बने रहेंगे।

आयोग के आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Vidyut Vinayamak Ayog (Rajya Sahkar Smiti) Vinayam, 2004, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 25th March, 2004

No. HPERC/021.—The following draft regulations, which the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 181, read with section 87, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, are hereby published, as required by sub-section (3) of section 181 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-171002.

DRAFT REGULATIONS

PART—I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (State Advisory Committee) Regulations, 2004.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (b) "Agenda" means the list of business proposed to be transacted at a meeting of the State Advisory Committee;
- (c) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;
- (d) "Commission" means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- (e) "Committee" means the State Advisory Committee;
- (f) "Committee Member" means a Member of the State Advisory Committee other than a Member of the Commission;
- (g) "Member" means a Member of the Commission.

(2) The words or expressions used, but not defined, in these regulations shall have the same meanings as are given to them in the Act.

PART—II

CONSTITUTION AND FUNCTIONS OF THE COMMITTEE

3. Constitution of the State Advisory Committee.—(1) The Commission shall, by notification, constitute with effect from such date, as it may specify in such notification, a Committee to be known as the State Advisory Committee.

(2) The Committee shall consist of not more than twenty-one nominated members to represent the interest, in the electricity sector, of:—

- (a) commerce,
- (b) electricity industry;
- (c) transport;
- (d) agriculture ;
- (e) labour;
- (f) consumers;
- (g) non-governmental organisations ; and
- (h) academic and research bodies in the electricity sector.

(3) The Commission may consult the representatives or bodies of interest groups before nominating the members, if it considers it necessary.

(4) The following shall be ex-officio Members of the Committee:—

- (a) the Chairperson of the Commission;
- (b) the Members of the Commission;
- (c) the Secretary to the State Government in-charge of the Ministry or Department dealing with the Consumer Affairs and Public Distribution System.

(5) The Chairperson of the Commission shall be the ex-officio Chairperson of the Committee.

(6) The Secretary of the Commission shall be the ex-officio Secretary of the Committee.

(7) The term of Committee Members, nominated under sub-regulation (2), shall be two years from the date of the notification of their appointment:

Provided that a nominated Committee Member shall be eligible for re-nomination.

4. *Functions of the State Advisory Committee.*—The functions of the Committee shall be to advise the Commission on—

- (a) major questions of policy;
- (b) matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensee;
- (c) compliance by licensees with the conditions and requirements of their licence;
- (d) protection of consumer interest;
- (e) electricity supply and overall standards of performance by utilities; and
- (f) matters which the Commission may refer specifically.

PART—III MEETINGS

5. *Meetings of the Committee.*—The Committee shall, for transaction of its business, meet once in every six months or at such intervals as may be decided by the Chairperson.

6. *Venue of Meetings.*—The meetings of the Committee shall be held at such places as may be decided by the Chairperson.

7. *Agenda and Notice of Meetings.*—(1) The Secretary of the Commission shall, after approval of the Chairperson, convene the meetings of the Committee by sending the agenda of the meeting together with notice, statements and report, if any, and by giving Members/

Committee Members thereof not less than fourteen (14) days notice in writing of the date, time and place of the proposed meeting.

(2) The members may write to the Secretary, indicating, through a brief note, any particular matter referred to in regulation 4, for inclusion in the agenda of the subsequent meeting and, if permitted by the Chairperson, the same shall be included in the agenda to be circulated under sub-regulation (1).

(3) A special meeting can be convened by the Chairperson, in which case the notice for the meeting may be less than three days.

(4) A notice shall be deemed duly issued if it is sent, by post or by a messenger, within the prescribed time to the registered address of the Member/Committee Member.

8. *Quorum for and discussions in Meetings.*—(1) The quorum for the meeting shall be one-third of the total strength of the Committee:

Provided that attendance by proxy shall not be permitted at the meeting of the Committee.

(2) If there is no quorum, the meeting shall stand adjourned and no further notice and quorum shall be required at the adjourned meeting :

Provided that if at any time after the meeting is commenced a quorum ceases to exist, the meeting shall not be dissolved but shall continue.

(3) No matter shall be considered at an adjourned meeting other than the matters remaining from the meeting at which the adjournment took place:

Provided that, with or without notice, the Chairperson may bring in, or direct to be brought before an adjourned meeting of the Committee any new matter which, in his opinion, is urgent.

(4) The discussions held and consequent conclusions, if any, drawn in the meeting shall strictly follow the agenda scheduled for the meeting:

Provided that the Chairperson may take up additional subjects to the agenda at the end of the meeting.

9. *Vacancies and non-receipt of agenda not to invalidate proceedings.*—No proceedings of the Committee or any resolution passed or any decision taken shall be invalid by reason solely of the vacancies existing in the Committee, or by reason of non-receipt, by any Committee Member, of the notice or the agenda papers, provided that the notice and agenda is duly issued.

10. *Presiding Officer.*—(1) The Chairperson shall preside over the meetings and conduct the business. If the Chairperson is unable to be present in the meeting, for any reason, the senior-most Member of the Commission shall preside over the meeting and perform the duties of the Chairperson of the Committee.

(2) The rulings given by the Chairperson, or the Member presiding over the meeting, on any points of procedure shall be final and binding.

11. *Participation of Meetings.*—(1) The Chairperson may invite any person, who is not member of the Committee, as a special invitee to aid and advise the Committee on any matter on the agenda of the meeting.

(2) The Secretary and such other person who is invited by the Chairperson to attend any meeting may, with the approval of the Chairperson or the presiding Member, participate in the discussions.

12. Minutes of Meetings.—(1) The Secretary, or in his absence an officer of the Commission designated by the Chairperson, shall record the minutes of the meetings and maintain a book, which will, amongst other things, contain the names and designations of the Members and invitees present in the meeting and proceedings thereof.

(2) The minutes of the previous meetings shall be confirmed in the next meetings and shall be signed by the Chairperson of the meeting.

(3) In relation to the decisions taken in the previous meeting the action taken report shall be laid by the Commission in the next meeting for the information of the members.

(4) The record of proceedings shall be open for inspection to the Committee Members.

(5) Any person, other than the Committee Member, may, on the payment of fees prescribed by the Commission for obtaining the certified copies of its record, be supplied with a copy of the record of the proceedings of the Committee.

PART—IV

FEES AND ALLOWANCES TO MEMBERS AND RESIGNATION/CESSATION OF MEMBERSHIP

13. Fees and travelling allowances for Committee Members.—(1) A Committee Member, including an invitee under regulation 11, shall not be entitled to any remuneration other than provided in these regulations.

(2) A Committee Member, including the invitee, who is a Government officer or an employee/officer of any Government instrumentality or of any Public Sector Undertaking, shall draw travelling and daily allowance from his parent department or organisation.

(3) All Committee Members, or an invitee, other than those referred to under sub-regulation (2) shall be paid a sitting fee of Rs. 500/- per meeting and the T. A. and D. A. at the rate admissible, in the State Government to its Grade-I officers.

(4) Whenever it is expedient to do so, the Commission may make Boarding and Lodging arrangements for the members coming from places outside the place fixed as the venue of the meeting and provide conveyance facility from and to the nearest railway station/airport.

14. Cessation of Membership.—(1) A nominated Committee Member who fails to attend two consecutive meetings of the Committee without prior information to the Commission and without any valid reasons for his absence shall forthwith cease to be a Committee Member.

(2) Any nominated Member, may, by writing under his hand addressed to the Secretary of the Commission, resign his office as a Committee Member, and such resignation shall come into effect from the day the Chairperson accepts the same.

(3) The Commission will take appropriate action to nominate a Committee Member to fill up the vacancy so caused and the term of the Committee Member nominated under this sub-regulation shall be coterminous with the term of office of the other Committee Members nominated under regulation 3 (2) of these regulations.

15. *Removal of Member.*—(1) The Commission may remove any Member of the Committee other than an ex-officio Member, who—

- (a) has been adjudged as insolvent; or
- (b) has been convicted of an offence involving moral turpitude; or
- (c) has become physically or mentally incapable of acting as a member; or
- (d) has conducted himself in the manner or has abused his position as to render his continuance as a member prejudicial to the public interest or to the object and purpose of the Act.

(2) The Member who is proposed to be removed under sub-regulation (1) shall be given an opportunity to represent his position to the Chairman of the Commission.

PART—V MISCELLANEOUS

16. *Power to remove difficulties.*—(1) Subject to the provisions of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and these regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions in regard to the implementation of these regulations and procedures to be followed on various matters, which the Commission has been empowered by these regulations to direct and matters incidental or ancillary thereto.

(2) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, by general or special order, do or undertake or permit the Committee to do or undertake things, which in the opinion of the Commission is necessary or expedient for removing the difficulties.

(3) Subject to the provisions of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Commission may, at any time, by an order, add, vary, modify or amend any of the provisions of these regulations.

(4) Every order made under this regulation shall be laid, as soon as may, after it is made, before the State Legislative Assembly.

17. *Repeal and savings.*—(1) The Guidelines for Functioning of the State Advisory Committee dated the 28th February, 2001 issued under sections 24 and 25 of the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 (Act No. 14 of 1998) by the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, the sitting Members of the Advisory Committee nominated under the repealed Guidelines shall continue as Members under these regulations for the remaining period of their term of office.

BY ORDER OF THE COMMISSION,

Sd/-
Secretary.